वित्तीय संसाधनों को सरकार से पाने के लिए नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर ने कसी कमर: खंडेलवाल

झांसी। देश के नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अलग से एक वित्तीय संरचना के गठन के उद्देश्य को लेकर हाल ही में गठित एक्शन कमेटी फॉर फॉर्मल फाइनेंस फॉर नॉन कॉर्पोरेट स्माल बिजनेस के राष्ट्रीय कोऑडिनेटर प्रवीन खंडेलवाल ने कहाकि देश में अब तक कॉर्पोरेट सेक्टर को सभी प्रकार के वित्तीय लाभ करों में कटौती और बैंकों से बडी मात्रा में लगातार कर्ज खुले हाथों से दिया गया, जबकि राष्ट्रीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान और देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र को वित्तीय कर्ज देने में बैंक और सरकार दोनों बुरी तरह असफल हुए। इन सब हालातों के बावजूद अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र कॉपोरेट सेक्टर से काफी आगे निकल गया।

पत्रकारों से वार्ता करते एक्शन कमेटी फॉर फॉर्मल फाइनेंस फॉर नॉन कॉर्पोरेट स्माल बिजनेस के राष्ट्रीय कोऑडिनेटर प्रवीन खंडेलवाल

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा इस वर्ष के बजट के पैरा 102 में नॉन कॉपरेट छोटे व्यापार के विकास के लिए एक सुदृढ़ ऋण व्यवस्था बनाने हेतु वित्तमंत्रालय, लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय और रिजर्व बैंक के अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने की घोषणा के संदर्भ में एक्शन कमेटी का गठन किया गया है। खंडेलवाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि उक्त कमेटी में नॉन कॉपरेट स्माल बिजनेस के सभी प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया ने बताया कि एक्शन कमेटी में कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, आल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ गडस व्हीकल ओनर्सएसोसियेशन, आल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसियेशन, फेंडरेशन ऑफ इंडियन स्माल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, भारतीय किसान मोर्चा, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, उत्तर प्रदेशव्यापार मंडल, बिजनेस डेवलपमेंट आर्गेनाइशन सहित अन्य अनेक संगठन शामिल हुए हैं। लगभग 6 करोड व्यापारिक प्रतिष्ठान, 1.25 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स, 4 करोड हॉकर्स स्व. रोजगार करने वाले लोगों, उदयमयी महिला उदमियों आदि का प्रतिनिधित्व करती हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के के राष्ट्रीय चेयरमैन महेन्द्र शाह ने कहाकि नॉन कॉपरेट सेक्टर की ऋण जरूरतों को पिछली सरकारों ने बेहद नजर अंदाज किया है जबकि देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वालंबी बनाने के लिए इस सेक्टर की ऋण आवश्यकताओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहाकि छोटा व्यापार ही वास्तव में बड़ा व्यापार है।

उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय पटवारी ने कहाकि देश का नॉन कॉर्पोरेट छोटे व्यापार का सेटर लगभग 49 करोड लोगों को रोजगार देता है जो देश के कुल रोजगार का 90 प्रतिशत है। दपेश की जीडीपी में 45 प्रतिशत का योगदान जो कॉर्पोरेट सेक्टर के योगदान से तिगुना है में केवल 4 प्रतिशत हिस्से को ही बैंकों से कर्ज मिल पाया है जबकि दूसरी ओर कॉर्पोरेट सेक्टर जिसे बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश और बैंकों इस असंख्य रूप से कर्ज मिला वह गत 20 वर्षों में कुल 22 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाया और जीडीपी में अपने हिस्से में केवल मात्र 3 प्रतिशत की ही वृद्धि कर पाया। वर्ष 1991 से वर्ष 2011 के 20 वर्षों के दौरान कॉर्पोरेट सेक्टर को 317 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है जिसमें से 176 बिलियन डॉलर स्टॉक मार्केट में और 141 विलियन डॉलर विदेशी निवेश के रूप में आया। यह आंकड़े खुद बताते हैं की पिछली सरकारों ने किस तरह केवल कॉर्पोरेट सेक्टर पर ही ध्यान दिया और अपनी नीतियां उन्हीं के अनुरूप बनाई।

कैंट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रमेश खन्ना ने बताया की नॉन कॉर्पोरेट छोटे व्यापार सेक्टर को ऋण मिलने हेतु एक मजबूत व्यवस्था के समर्थन में एक्शन कमेटी अगले दो महीने के भीतर देश भर में एक व्यापक अभियान शुरू कर रही है जिसके अंतर्गत देश के सभी राज्यों में बडे पैमाने पर जन अदालत, वर्कशॉप, सेमिनार आयोजित कर छोटे व्यापार को कथित रूप से मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं का खाका खींचा जायेगा। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, लघु एवं सूक्ष्म उपक्रममंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रमुख राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और संसद के दोनों सदनों के सांसदों को एक ज्ञापन दिया जायेगा।

व्यापारी नेताओं ने यह भी बताया कि बैंकिंग और वित्त विशेषज्ञ, अर्थशास्त्रियों और अर्थव्यवस्था से जुडे अन्य लोगों के साथ देश भर में गोल मेज सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। जन अदालतों में लोगों से पूछा जायेगा कि की क्या उन्हें बैंकों से ऋण मिल पाता है और मिलता है तो उसमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनकी राय में क्या नॉन कॉर्पोरेट छोटे व्यापार के लिए मजबूत कर्ज व्यवस्था जरूरी है अथवा नहीं है। इस रायशुमारी के आधार पर एक विस्तृत श्वेत पत्र तैयार किया जायेगा एक्शन कमेटी देश के विभिन्न राज्यों में 30 जन अदालत और 10 गोल मेज सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके अलावा अभियान में सोशलमीडिया का भी भरपूर उपयोग किया जायेगा वहीं दूसरी ओर कमेटी अपनी बेबसाइट के माध्यम से भी देश भर में लोगों से संवादकायम करेगी। नॉन कॉपरेट छोटे व्यापार को देश भर में कर्ज कैसे मिलता है। और क्यों एक मजबूर कर्ज व्यवस्था इस सेक्टर के लिए आवश्यक है को लेकर सारे देश में एक सुनियोजित पब्लिसिटी अभियान भी शीघ्र ही शुरू किया जायेगा। इस अवसर पर राम प्रकाश शर्मा, जिलाध्यक्ष अरूण गुप्ता, संतोष साहू आदि उपस्थित रहे।